The Chairman indicated that the suggestions of the State Labour Ministers would be kept in view while formulating proposals for the Comprehensive Industrial Relations Law.

बर्मा, चीन और बंगलादेश के साथ सीमा विवाद

2291. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा, चीन और बंगलादेश के साथ सीमा विवादों को निपटाने के लिए क्या नये प्रयास किये गये है ;

(ख) आपसी बातचीत के माध्यम से सीमा विवादों को निपटाने में सम्बद्ध सरकारों ने किस प्रकार की सहायता की है; और

(ग) आपसी समझौते से अब तक किन विवादों का निपटाया गया है, उनका ब्यौरा क्या है और बाकी विवादों को निपटाने में क्या कठिनाइयां सामने आ रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) से (ग). बर्मा के साथ सीमा के सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नही है । 1967 के करार के अन्तर्गत दोनों के बीच सयुक्त रूप से भूमि की सीमा का अकन किया जा रहा है ।

जहा तक चीन का प्रश्न है, उसके साथ हम पचशील के सिद्धान्तों के आधार पर सम्बन्धो को सामान्य बनाने के प्रयत्नों का तो स्वागत करते है लेकिन भारत-चीन सीमा की पुरानी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बगलादेश का जहां तक सम्बन्ध है, उसके साथ सीमा के अंकन से सम्बन्द्ध विवादों का निपटारा हो गया था और 16 मई, 1974 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने जिस करार पर हस्ताक्षर किए थे उसमें ठोस सिद्धान्त और क्रिया विधि का समावेश किया गया था । दोनों पक्षों के अधिकारियो द्वारा वास्तविक सीमांकन का कार्य भी चल रहा है ।

इजरायल को मान्यता

2292. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या विदेश मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल को मान्यता देने के बारे में कोई नया प्रस्ताव उस देश से सरकार को प्राप्त हुआ है, और

(ख) क्या इजरायल के साथ राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में सरकार कोई नई कार्यवाही कर रही है और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) जी नही ।

(ख) जी नहीं । पश्चिम एशिया की स्थिति में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है कि इजरायल के साथ अपने सम्बन्धो के संदर्भ में हमारे लिए पुनर्विचार करना जरूरी हो ।

2500 की जनसंख्या वाले गांवों में पूर्ण डाक-घरों की स्थापना

2293. **श्री केशवराव धोंडगे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो हजार से अधिक की जन संख्या वाले ग्रामों में पूर्ण डाकघर और पांच हजार से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों में टेलीफोन सुविधायें देने की योजना की सरकार ने घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में उक्त योजना को क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ग) ये सुविधायें देश भर में कब तक दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुखदेव साय) : (क) दो हजार से अधिक आबादी वाले अधिकांश गांवों में डाकघर खोल दिये गये है। 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधा देने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). (i) दो हजार से अधिक की आबादी वाले 40,702 गावों मे डाकघर काम कर रहे है।

(ii) पाच हजार से अधिक की आबादी वाले 7000 गावों में टेलीफोन की सुविधायें दे दी गई है।

(iii) ऐसा प्रस्ताव है कि अगले दो वर्षों मे 5000 से अधिक की आबादी वाले अधिकांश गावो मे टेलीफोन की सुविधायें दे दी जायें। शेष स्थानों पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आगामी वर्षों में ये सुविधायें उपलब्ध करा दी जायगी।

पड़ोसी देशों के साथ भारत में शरण लिये गये उनके नागरिकों के बारे में बात चीत

2294. **श्री केशवराव धोंडगे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बर्मा के साथ भारत में शरण लिये गये उनके नागरिकों को वापस भेजने के बारे में बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन सरकारो की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधाये देना

2295. **श्री युवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को जहा अन्य सब सुविधाए उपलब्ध है वहा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध नही है ;

(ख) यदि हा, तो यह सुविधा उन्हे कब तक दे दी जायेगी ; और

(ग) यदि नही, तो इस के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन के अन्य कर्मचारियों पर लागू नही होती है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नही उठते।

Reopening of Aluminium Corporation of India Ltd. Asansol

2296. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government is consulting with the Government of West Bengal in the matter of reopening of Aluminium Corporation of India Ltd., Asansol which is under lockout since 1974; and

(b) if so the present position of restarting of the above company?